मोदी ने मेरठ से फूंका चुनावी बिगुल

पश्चिम यूपी के राजनीतिक गढ़ मेरठ से बोला विपक्षी दलों पर हमला, बोले- भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं

अर्चिस मोहन

मेरठ से अरुण गोविल तथा बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना और बिजनौर के उम्मीदवारों को वोट की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जाट बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में रैली कर लोक सभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। उन्होंने वादा करते हुए कहा कि नई सरकार अपने पहले सौ दिनों के भीतर बड़े फैसले लेगी। मोदी ने कहा कि पिछले दस वर्षों के उनकी सरकार के कार्यकाल में लोगों ने अभी ट्रेलर ही देखा है। जो कभी असंभव समझा जाता था, उनकी सरकार ने संभव कर दिखाया। उन्होंने कहा अगले पांच वर्षों में विकास की नई रफ्तार देखने को मिलेगी।

मेरठ से अपना अलग रिश्ता जोड़ते हुए मोदी ने कहा, 'साथियों मेरठ की इस धरती के साथ मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। आपको याद होगा 2014 और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत इसी मेरठ से की थी। अब 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ में ही हो रही है।' इस रैली में रालोद प्रमुख और चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत सिंह चौधरी की मंच पर मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की कोशिशों से गन्ना किसानों को अपनी फसल की बेहतर कीमत मिलना सुनिश्चित हुआ है।

मोदी ने यहां पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को नमन करते हुए मेरठ से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल समेत बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना और बिजनौर के राजग उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील की और कहा कि चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न पड़े, आप लोग वोट देने जरूर जाना। टीवी धारावाहिक 'रामायण' सीरियल में राम की भूमिका निभाकर विख्यात हुए अभिनेता और मेरठ लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल भी चुनाव अभियान का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी थे।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, '2024 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने, कौन न बने, इसका चुनाव नहीं है। यह चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। यह चुनाव देश को अगले पांच वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा।' उन्होंने लोगों से कहा कि राजग को लोक सभा चुनाव में 400 सीटों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बढ़-चढ़ कर मतदान करें।

इस बीच उन्होंने विपक्षी दलों के समूह 'इंडिया' गठबंधन पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि 'भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है, उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। यदि आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाए और सरकार बड़े फैसले ले, किसान समृद्ध हों, महिलाएं सशक्त बनें और गरीब और युवाओं का कल्याण हो तो भाजपा और राजग उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करें।'

यहां केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के मैदान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों, राष्ट्रीय लोकदल (रालोद), अपना दल (एस), निर्बल शोषित इंडियन हमारा आम दल (निषाद) और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्षों के साथ मंच साझा करते हुए मोदी ने सबको राम-राम (पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभिवादन का तरीका) किया।

भाजपा ने वर्ष 2014 के लोक सभा के चुनाव में पश्चिमी यूपी में दमदार प्रदर्शन किया था। पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी ने 71 सीटें जीती थी। यह अलग बात है कि 2019 के चुनाव में पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले जैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा पायी। सपा, बसपा और रालोद ने उसे कड़ी टक्कर दी और भाजपा नगीना, रामपुर, अमरोहा, सहारनपुर, मुरादाबाद और बिजनौर सीटें हार गई थी। मोदी ने भरोसे के साथ कहा, 'हमारी सरकार भी तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है। हम आने वाले पांच साल का रोड मैप बना रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद पहले सौ दिनों में हमें कौन- कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इस पर तेजी से काम चल रहा है।'

कांग्रेस ने संवेदनहीन तरीके से दिया कच्चातिवु

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया में आई खबरों के हवाले से आज कहा कि नए तथ्यों से पता चलता है कि कांग्रेस ने कच्चातिवु द्वीप 'संवेदनहीन' ढंग से श्रीलंका को दे दिया था। उन्होंने 'एक्स' पर एक खबर साझा करते हुए कहा, 'आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली खबर। नए तथ्यों से पता चलता है कि कांग्रेस ने कैसे संवेदनहीन ढंग से कच्चातिवु दे दिया था। इससे प्रत्येक भारतीय नाराज है।'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना कांग्रेस का 75 वर्ष से काम करने का तरीका रहा है।' केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है।

दूसरी ओर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि चुनाव से ऐन पहले प्रधानमंत्री इस संवेदनशील मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन आपकी ही सरकार के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने 2014 में उच्चतम न्यायालय को बताया था कि कच्चातिवु 1974 में एक समझौते के तहत श्रीलंका गया था। **भाषा**

केजरीवाल, सोरेन को शीघ्र रिहा किया जाए : विपक्ष

अर्चिस मोहन

इंडियन नैशनल डेवलपमेंट इनक्लूसिव अलायंस (इंडिया) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शीघ्र रिहा करने की मांग की है। विपक्षी गठबंधन की दिल्ली के रामलीला मैदान में आज आयोजित रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गठबंधन की पांच मांगें रखीं। गठबंधन ने निर्वाचन आयोग से लोक सभा चुनाव के दौरान सभी को समान अवसर सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया।

विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई का दुरुपयोग रोकने के लिए हस्तक्षेप करने को भी कहा। रैली में शामिल विपक्षी नेताओं ने कहा कि सरकार आर्थिक मोर्चेबंदी कर विपक्ष का गला घोंटना चाहती है। इसे रोका जाए। उन्होंने चुनावी बॉन्ड मामले को बड़ा घोटाला बताया और इसकी जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल से कराने की मांग की।

इससे पहले रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यदि 2024 के लोक सभा चुनाव में भाजपा विजयी होती है तो वह संविधान को बदल देगी और भारत विखंडित हो जाएगा। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी रैली को संबोधित किया। केजरीवाल और सोरेन के साथ एकजुटता दर्शाने के लिए रैली के मंच पर दो सीटें खाली रखी गई थीं। रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत विपक्षी गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने संबोधित किया। सुनीता ने अपने पति की ओर से लिखा गया देशवासियों के नाम संदेश भी पढ़कर सुनाया। इसमें उन्होंने देश के गरीबों को चौबीसों घंटे मुफ्त बिजली, प्रत्येक जिले में बहुदेशीय अस्पतालों के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी एवं सस्ती शिक्षा, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किसानों को एमएसपी तथा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही है।

रामलीला मैदान में एकजुटता

- दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली को राहुल समेत कई विपक्षी नेताओं ने किया संबोधित
- केंद्रीय निर्वाचन आयोग से लोक सभा चुनाव में सभी को समान अवसर सुनिश्चित कराने व एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने का किया आग्रह

एआईएमआईएम और अपना दल का नया गठबंधन

सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की जंग के बीच उत्तर प्रदेश में कुछ छोटे दलों ने मिलकर एक नए मोर्चे का गठन किया है। पल्लवी व कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ मिल कर पीडीएम के नाम से नया गठबंधन बना लिया है। **बीएस**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda Hamesha Aapke Liye
www.bankofbaroda.in

निविदा सूचना

बैंक ऑफ़ बड़ौदा निम्नलिखित के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है:

बैंक की शाखाओं/ कार्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर, एंटी-वायरस सॉफ़्टवेयर और सहायक उपकरणों की आपूर्ति, इंस्टॉलेशन एवं रखरखाव के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध।

(उपर्युक्त निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख **22 अप्रैल, 2024 को अपराह्न 03:00 बजे तक है**)

विस्तृत विवरण बैंक की वेबसाइट: www.bankofbaroda.in पर निविदा खंड एवं GeM प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है।

"अन्य सूचना", यदि कोई हो, बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर निविदा खंड के अंतर्गत प्रकाशित किया जाएगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीकर्ताओं को इसे अवश्य देखना चाहिए।

स्थान: मुंबई
दिनांक: 01.04.2024

मुख्य महाप्रबंधक (आईटी)

(152 / 23-24)

भारतीय रिजर्व बैंक के 90 साल

रिजर्व बैंक का शानदार सफर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मौद्रिक नीति बनाने और बैंकों को विनियमित करने की दोहरी भूमिका निभाता है। सोमवार को आरबीआई अपने 90वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इस अवसर पर मुंबई के नैशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में होने वाले एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। अप्रैल 2015 के बाद आरबीआई के किसी कार्यक्रम में मोदी की यह पहली भागीदारी होगी। उन्होंने आरबीआई की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित वित्तीय समावेशन सम्मेलन में भाग लिया था। आरबीआई के 90 वर्षों के सफर का जायजा ले रहे हैं **मनोजित साहा:**

रिजर्व बैंक ने हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को अपना परिचालन शुरू किया था।

सर ओसबोर्न स्मिथ रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे और उनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 के बीच रहा। उन्होंने एक पेशेवर बैंकर के तौर पर बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स में करीब 20 वर्षों तक काम किया था। इसके अलावा उन्होंने कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी 10 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी थीं। उसके बाद 1926 में वह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग गवर्नर के रूप में भारत आए थे। आरबीआई अन्य तमाम केंद्रीय बैंकों के विपरीत एक फुल सर्विस केंद्रीय बैंक है।

शुरू में आरबीआई ने कृषि पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही योजना अवधि की शुरू होने पर आरबीआई ने विकास को रफ्तार देने के लिए वित्त के उपयोग की अवधारणा को आगे बढ़ाया। उसने देश में वित्तीय बुनियादी ढांचा विकसित करने के क्रम में निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जैसे कई संस्थानों की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू होने के साथ ही आरबीआई का ध्यान मुख्य तौर पर मौद्रिक नीति, बैंकों के पर्यवेक्षण एवं विनियमन, भुगतान प्रणाली की देखरेख और वित्तीय बाजारों के विकास जैसे केंद्रीय बैंकिंग कार्यों पर केंद्रित हो गया।

प्रमुख तथ्य

बर्मा (म्यांमार) 1937 में भारत संघ से अलग हो गया, मगर आरबीआई ने बर्मा पर जापानी कब्जे तक और बाद में अप्रैल 1947 तक बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में काम करना जारी रखा।

भारत के विभाजन के बाद आरबीआई ने जून 1948 तक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का परिचालन शुरू होने तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया।

भारतीय सिविल सेवा के सदस्य सर बेनेगल रामा राव ने अगस्त 1949 से जनवरी 1957 के बीच सबसे लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर के तौर पर अपनी सेवाएं दी।

मनमोहन सिंह 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रहे और वह देश के वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री (2004 से 2014) भी बने।

ऊर्जित पटेल 2018 में पिछले 43 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले आरबीआई गवर्नर थे।

शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। वह इस साल दिसंबर में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के बाद सर बेनेगल रामा राव के बाद सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गवर्नर बन जाएंगे।

प्रमुख घटनाक्रम

- 1 अप्रैल 1935 से कामकाज शुरू।
- 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसे मूल रूप से एक शेयरधारक बैंक के रूप में स्थापित किया गया था।
- उसी साल भारतीय रुपये का पहली बार अवमूल्यन किया गया। उसके बाद 1966 में और 1991 में रुपये का अवमूल्यन किया गया।
- 1966 में आरबीआई ने सहकारी बैंकों का विनियमन शुरू किया।
- 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
- विदेशी मुद्रा के संरक्षण के लिए 1973 में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) लागू हुआ।
- 1977 में एम1, एम2, एम3 की अवधारणाओं के तहत रकम आपूर्ति की एक नई श्रृंखला पेश की गई।
- 1985 में मौद्रिक प्रणाली के कामकाज की समीक्षा के लिए एस. चक्रवर्ती समिति स्थापित। उसकी सिफारिशों के दूरगामी परिणाम हुए।
- 1988 में अधिकतम उधारी दर खत्म कर दी गई। बैंकों को ग्राहकों से उनके क्रेडिट रिकॉर्ड के अनुसार शुल्क लेने की आजादी दी गई।
- 1991 में बीओपी संकट के बीच आरबीआई ने भंडार बढ़ाने के लिए सोना गिरवी रखा, रुपये का अवमूल्यन हुआ।
- 1993 में निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए, दस नए बैंक स्थापित किए गए।
- 1997 में आरबीआई और भारत सरकार राजकोषीय घाटे के स्वतः मुद्रीकरण को समाप्त करने के लिए एडहॉक ट्रेजरी बिल की व्यवस्था को अग्रिम से बदलने पर सहमत हुए।
- 1999 में नकदी पर दबाव कम करने के उद्देश्य से डेबिट कार्ड पर दिशानिर्देश जारी किए गए।
- 1999 में बाहरी व्यापार एवं भुगतान की सुविधा के लिए फेरा की जगह फेमा को लागू किया गया।
- 2001 में इंटरनेट बैंकिंग दिशानिर्देश जारी किए गए।
- 2007 में भुगतान एवं निपटान प्रणाली के लिए नियामक बने।
- 2014 में 10 साल के बाद दो नए बैंक लाइसेंस जारी किए गए।
- 2015 में भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंकों की स्थापना के लिए बैंक लाइसेंस जारी किए गए।
- 2016 में यूपीआई को परीक्षण के तौर पर शुरू किया गया।
- 2016 में मुद्रास्फीति लक्ष्य को अनिवार्य बनाते हुए मौद्रिक नीति समिति का गठन।
- 2016 में केंद्रीय बोर्ड ने काले धन को खत्म करने के लिए नोटबंदी के विवादास्पद फैसले को मंजूरी दी। इससे एक ही झटके में प्रचलन में 87 फीसदी मुद्रा अमान्य हो गई।
- 2019 से 2020 से एनईएफटी और आरटीजीएस को सातों दिन चौबीसों घंटे परिचालन में हैं।
- 2022 में पहली बार मुद्रास्फीति अनुमान तक पर खरा नहीं उतरी।
- 2022 में परीक्षण के तौर पर केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की शुरुआत।